

क्षेत्र-शक्ति

वर्ष 2 अंक 2

दिल्ली

माचं-अप्रैल 1987

इस अंक में

2. बोध 87
3. बिहार में नारी जीवन
7. New Education Policy & DMS
9. Foreign Students : Their Problems

राष्ट्रीय क्षेत्र शक्ति

सम्पादक

संजय सम्पादकी

सम्पादकीय सहकर्मी
राकेश सिन्हा, संजय चौधरी

प्रकाशन कार्यालय
४२२/३६७६, रंगरपुरा,
हरियाणा सिटी मार्ग
करोल बाग, नई दिल्ली-११००५
दूरभाष : 528215

परीक्षाओं का बहिष्कार टला

ऐसा लग रहा था कि अगर अगले 10-15 दिनों में मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर कालेज-शिक्षकों का वेतनमान नहीं बढ़ा तो दिल्ली विश्व-विद्यालय में परीक्षाओं के बहिष्कार को टाला नहीं जा सकता। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) नए वेतनमान की घोषणा की मांग को लेकर हलचलें करता रहा है। लेकिन सरकार कान में तेल डाले बैठी रही। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लगभग सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और अफसरों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। अब बचे हैं स्कूली शिक्षक और कालेज के प्राध्यापक। स्कूली शिक्षकों की लम्बी हड़ताल हुई। परीक्षाओं का बहिष्कार भी हुआ। जमकर नकल बगैरह हुई, मेधावी छात्र-छात्राओं के भविष्य पर कितना असर पड़ा होगा, राम जाने।

'DUTA' ने भी आगामी परीक्षाओं के बहिष्कार का मन बनाया था। 19 मार्च को 'DUTA' कार्यकारिणी की बैठक में यह तय किया गया कि इस विषय पर हर कालेज की स्टाफ काउंसिल की राय ली जाय। 27 मार्च को पुनः DUTA कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें परीक्षा बहिष्कार का फैसला लिया गया। लेकिन 11 अप्रैल को विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की आम सभा में अन्तिम समय में फैसला बदल दिया गया। छात्र हितों को ध्यान में रखकर और छात्र समुदाय के दबाव के कारण परीक्षा-बॉयकाट न करने का फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है।

अब DUTA पूरे देश के शिक्षकों के साथ मिलकर जुलाई-अगस्त महीने में हड़ताल करेगी।

बोध-८७

दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे वर्ष लगातार कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। लेकिन यह विश्वविद्यालय की विरम्बना है कि विश्वविद्यालय में वार्षिक कार्यक्रम पटा-भटा ही देखने को मिलते हैं। इसी हिसाब में ही 17 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव श्री नरेन्द्र टंडन द्वारा छात्रों के वार्षिक स्तर को उठाने के लिए बोध-87 नाम से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए लगभग सभी कमिटी से छात्रों को लेकर आयोजन समिति का गठन किया गया, कार्यक्रम को सफलता की चरम सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय प्राध्यापकों का भी सहयोग लिया गया।

प्रतियोगिता (परीक्षा) के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 केंद्रों की व्यवस्था की गई जो क्रमशः न्यू कम्बो-केंचन हॉल, पी० जी० डी० ए० वी० कॉलेज, राजधानी कॉलेज, श्याम लाल कॉलेज, ए० आर० एस० डी० कॉलेज थे। लगभग 16 पृष्ठों के परीक्षा पत्र को बोध-87 परीक्षा को हल करने के लिए लगभग 2090 छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षा में प्रथम पुरस्कार 750 रु., द्वितीय 500 रु. का, तृतीय 300 रु. व 50 सांत्वना पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों में यह पहला ऐसा

वार्षिक कार्यक्रम था जिसमें 2000 के ऊपर छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी में उत्साह को देखकर आयोजकों के मनोबल को भी ठोस आधार व उत्साह मिला।

परीक्षा के 12 दिन पश्चात् 2 मार्च को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन में हुआ। पुरस्कार वितरण दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० मुनिश रजा के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। संघ को सहायक निदेशक तकनीकी शिक्षा श्री सुरेन्द्र सिंह, समाजिक कार्यकर्ता श्री केशर नाथ, व छात्र संघ सचिव श्री नरेन्द्र टंडन ने सुशोभित किया।

प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता रामजस कालेज के राजकुमार, द्वितीय पुरस्कार विजेता श्री अशोक बबुटा व तृतीय कु० बीना गुप्ता हिंदू कालेज व कु० सीमा रही। 66 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए।

कार्यक्रम में बोलते हुए कुलपति प्रो० मुनिश रजा ने कार्यक्रम के आयोजक की सराहना की व कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक स्तर को उठाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का धृंखलाबद्ध आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की मानसिकता के दायरे को ऐसे कार्यक्रमों द्वारा व्यापक किया जा सकता है।

—पायल भागी

श्रद्धांजलि

मूर्धन्य साहित्यकार श्रीरामन्द सच्चिदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय के देहावसान के साथ हिन्दी साहित्य का एक युग समाप्त हो गया। अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में उनकी सफलता ने उन्हें साहित्यिक महामानव बनाया। हिन्दी नईकविता के वे जनक थे, कथा को उन्होंने नया शिल्प दिया एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिष्ठा

अर्जित की। उनकी यायावरी वृत्ति, उनका सौन्दर्य बोध और उनकी अनुभव सम्पन्नता ने साहित्य को अद्भुत समृद्धि दी।

प्रखिल भारतीय वि० प० के अनेक कार्यक्रमों में उपस्थित होकर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उस महामानव को आज हम हृदय से याद करते हैं। □

बिहार में नारी जीवन : एक विभिषिका

भगवान राम ने एक सीता के लिए पूरी लंका जला दी, तो हजारों नारियों की दयनीय स्थिति पर सम्पूर्ण समाज चुप क्यों? यह स्पष्ट सवाल छात्र चंपारण (बिहार) की छात्रा ने पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया है।

हजारों छात्राओं के मन में व्याप्त यह प्रश्न समाज के सामने एक आह्वान के रूप में लड़ा करने के उद्देश्य से बिहार में अनेक स्थानों पर अ० भा० विद्यार्थी परिषद ने छात्रा सम्मेलन आयोजित किये थे। जिसमें हजारों की संख्या में छात्राएँ उपस्थित थीं। महाराष्ट्र से गयी हुयी चार छात्राओं ने दो गुटों में उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार का प्रवास किया। जिसमें प्रमुख रूप से पटना, कटिहार, दरभंगा, रांची, टाटानगर, हजारीबाग, गुमला आदि स्थान शामिल थे। बिहार में स्त्री की भयावह स्थिति का अनुभव इन छात्राओं को पटना की घोर जाते समय ट्रेन में ही महसूस होने लगा। बिहार में दहेज, बालविवाह, अत्याचार, अशुभ, अश्लीलता आदि समस्याओं से ग्रस्त, असहाय महिलाओं से प्रत्यक्षतः मिल कर इन छात्राओं ने उनके दुःख-दर्द को महसूस किया। प्रवास में एवं कार्यक्रमों द्वारा अनेक छात्राओं से, परिवारों से मिलने का इनको जब मौका मिला, बातचीत हुई, विश्वास बढ़ गया और वास्तविकता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो ध्यान में आया कि केवल कल्पना के आधार पर बिहारी स्त्री की सचस्थिति संघ सुदूर महाराष्ट्र में रहने वाली स्त्री अनुभव नहीं कर सकती।

बिहार में स्त्री जीवन की अशुभ का सबसे महत्वपूर्ण कारण है 'दहेज'। हर बारह घंटे में एक दहेज मौत यहाँ की परम्परा है। इससे दहेज समस्या की तीव्रता का अहसास होता है। दहेज केवल शादी के समय ही नहीं लिया जाता बल्कि तीन प्रकार के दहेज लेकर तीन बार उस बहू को परेशान किया जाता है। शादी के पहले होता है 'तिलक दहेज' शादी में 'दहेज' और शादी के एक

साल बाद 'माँग दहेज' लिया जाता है। और इसी कारण बिहार की स्त्री कहती है कि शादी के बाद कम से कम एक साल तो हमारी बहूबेटियाँ सुरक्षित रहती हैं। समाज में तथाकथित उच्चवर्ग के लोग दहेज को प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं। छोटा तबका इससे थोड़ा अलग रहता है। लेकिन रस्तीतान होती है मध्यम वर्गीय समाज की। जिसको एक तरफ चिंता रहती अपनी प्रतिष्ठा की और दूसरी तरफ अपनी धामदनी की। चार छात्राओं के इस प्रश्न ने 'दहेज' विषय पर पद्य-नाट्य भी स्वान-स्थान पर सादर किया। प्रदर्शन एवं धाम सभाओं में भी दहेज के खिलाफ आवाज उठायी कटिहार में वहाँ के महाविद्यालय प्राचार्य सुधी रानी देवी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया की दहेज पद्धति को विरोध करने के कारण अभी तक उनकी शादी नहीं हो सकी है। वहाँ की छात्रा इस पद्धति का विरोध जबरन करना चाहती है लेकिन सक्षम स्त्री नेतृत्व की कमी, एवं माता-पिताओं द्वारा 'दहेज' को ही शादी का प्रमुख आधार मानना उनके लिए जुलम बन गया है।

आज बिहार में अश्लील साहित्य, चित्रपट, पोस्टर्स आदि की माँग तेजी से बढ़ रही है। संस्कारहीन समाज का यह प्रमाण है इसके कारण स्त्री का मान सम्मान दिन ब दिन समाप्त होता जा रहा है और केवल पैसा प्राप्त करने की दृष्टि रखने वाली स्त्री ही इसके कुछ हद तक जिम्मेवार है। छोटा नागपुर जो खनिज संपदा से भरपूर है। लेकिन वहाँ की स्त्री अनेक विधि समस्याओं से घिर गयी है। बालविवाह एक ऐसी ही समस्या है। यहाँ होने वाली कुल शारिणों में से सत्तर प्रतिशत बालविवाह होते हैं। छोटा नागपुर आदिवासी इलाका है। यहाँ की स्त्री शिक्षा से वंचित है। लड़कियों की छेदलानी, लड़कियों को भगा ले जाना, उन्हें गलत काम के लिए मजबूर करना यहाँ

(शेष पृष्ठ चार पर)

जायज है लेकिन...

घाजादी के बाद से ही हिन्दी प्रेम का डोल सरकारी घोर और सरकारी स्तर पर पीटा जाता रहा है। घंघेजी की जगह हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के राष्ट्रीयता भाषण की भी घाए दिन रेखांकित किया जाता है। सन 84 के आम चुनाव में विद्याल बहुमत पाकर सत्ता संभालने वाली राष्ट्रीय सरकार के लिए तो राष्ट्रीयता ध्वजता घोर राष्ट्रीय प्रेम खास मुद्दे रहे हैं। हिन्दी के विकास-विस्तार के लिए सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए फूंकती भी रही है। सरकारी विभाग में हिन्दी पत्रबाह, हिन्दी दिवस, गोष्ठियों आदि आयोजन होता ही रहता है। राजनेता घोर प्रशासनिक अधिकारी गहरे-वेगाहे हैं हिन्दी के उत्थान के लिए भाषण (घंघेजी में ही सही) भाड़ते रहे हैं। लेकिन इसी सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में इंच-दर-इंच जगह पाने के लिए हिन्दी भाषियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। घाई. आई टी. दिल्ली के ध्यामरुद्र पाठक की कथा-व्यथा का अध्याय पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ है कि घब पुष्पेन्द्र चौहान नामक एक नौजवान वकील की गुहार नकार खाने में तूती की आवाज की तरह गूंज रही

पृष्ठ तीन का शेष

की घान बात है। शाम 5 बजे के बाद अकेली स्त्री कहीं भी नहीं जा सकती। यहाँ की छात्रा सिर्फ मानिग शो देख सकती है। बस में भी केवल दो सीटें महिलाओं के लिए और वह भी लगभग चौबीस घण्टे खाली रहती है। यहाँ सह शिक्षा (Co-Education) की पद्धति असम्भव है। लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय, महाविद्यालय उपलब्ध है।

इन सब समस्याओं से मुक्त होने लिए आवश्यक धैर्य तथा आत्म विश्वास प्राप्त हो सकता है, शिक्षा से। लेकिन स्त्री शिक्षा का वर्तमान प्रतिशत है केवल 17% और उसमें भी समाज का स्त्री शिक्षा की घोर देखने का दृष्टिकोण विचित्र है। समाज में शिक्षा को व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक यह मान्यता नहीं बल्कि शिक्षा है शादी

है। उसे लगभग बीसेक दिन बोट बलब पर घनघन करना पड़ा। इससे पहले उसने हर छोटी-बड़ी इगोड़ी पर पहुंच कर अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन घंघेजियत की खमारी में संबंधित पक्ष ने उसकी एक न सुनी। श्री चौहान की बड़ी साधारण सी मांग है। वह देशी भाषा में वकालत करना चाहता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अधिवक्ता के नाते पंजीकरण कराना चाहा लेकिन बार काउंसिल ने उसे पंजीकृत करने से इंकार कर दिया। कहा गया—'गहने घंघेजी भाषा में परीक्षा पास करके दिलाओ फिर वकालत करने की सोचना। यही से वह जद्दो जहद शुरू होती है जिसका दूर-दूर तक घन्त नहीं दीखता। करीब बीस दिन की भूख हड़ताल और विभिन्न राष्ट्रवादी छात्र-युवा संगठनों के दबाव के कारण दिल्ली बार काउंसिल ने श्री चौहान के मामले पर गौर (?) करने का आश्वासन तो दिया है। देखना है ये इस काम में कितना समय लगाते हैं।

इस पूरे प्रकरण में सरकारी तंत्र (खासकर शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय) की चुप्पी विशेष रूप से घलरती है।

दिनेश पाहूजा

की सीदे बाजी के लिए एक प्रतिरिपत पात्रता (क्वालिफिकेशन)। अपने वच्चों पर सुसंस्कार करने वाली माँ ही आज स्वयं घजान के घन्घेरे में फँसी हुई है।

बिहार की नारी जिस भयावह दौर से गुजर रही है उसे समाज के सामने प्रस्तुत करने छात्राओं के सम्मेलन, प्रदर्शन, ग्राम सभा, दहेज प्रतिमा एवं अश्लील पोस्टरों के दहन आदि कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद ने इस नारी जागरण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किये थे। आज तक बिहारी छात्राओं को अपनी समस्याओं के प्रति आवाज उठाने को कोई मंच उपलब्ध नहीं था। विद्यार्थी परिषद ने इस अभियान के द्वारा यह मंच उपलब्ध कर दिया है। भविष्य में भी इस समस्या के प्रयत्नशील रहने का निश्चय करते हुये यह छात्राएँ वापस महाराष्ट्र लौट गयीं।

—धीकांत

एक और शहादत

करीमनगर :

घान्ध प्रदेश में करीमनगर जिला के जमीकुरा गाँव के ६० सामीरेडुडी की हत्या कर दी गई है। वे वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में अध्यापक थे और विद्यार्थी परिषद् की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष थे। 6 फरवरी को नक्सलियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। उनकी शवदाफा में करीब 15 हजार ग्रामवासियों ने भाग लिया। हत्या के विरोध में 9 फरवरी को करीमनगर जिला पूरी तरह बन्द रहा।

घान्ध प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रवादी ताकतों के बढ़ते प्रभाव से बेचैन नक्सली प्रबन्धन भगड़े पर उतारू हो गए हैं। इससे पूर्व भी प्रदेश में विद्यार्थी परिषद् सहित कई राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। तेलगू देशम मंत्रिमंडल के एक सदस्य के सक्रिय संरक्षण के कारण नक्सली कानूनी पकड़ से बाहर निकल घाते हैं।

हाल में स्थानीय कॉलेज यूनियन के चुनाव में परिषद् कार्यकर्ताओं को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। इसी से बौखला कर नक्सलियों के 'पोपुल्स वार ग्रुप' ने परिषद् के इकाई अध्यक्ष की हत्या की है। सतारूड तेलगू देशम का स्थानीय विधायक प्रबन्धन इन अपराधियों को बचाने में सहयोग दे रहा है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है।

रोहतक

प्रखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की रोहतक शाखा ने स्थानीय लालनाथ हिन्दू कॉलेज (महिला विभाग) के

प्राण में रोहतक के सभी महाविद्यालयों के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए "निःशुल्क शिक्षा प्रकल्प" शुरू किया है। "निःशुल्क शिक्षा प्रकल्प" के प्रमुख मुमन शर्मा के अनुसार ट्यूशन की वर्तमान दर 200 रुपये से 400 रुपये तक हो गई है, जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिये असहनीय है। छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें विषय की अच्छी जानकारी मिल सके और सुयोग्य प्राध्यापकों का मार्ग दर्शन सहज मुलभ हो सके, इसलिए इस प्रकल्प की शुरुआत हुई है।

अमृतसर

विद्यार्थी परिषद् की स्थानीय शाखा ने 3 फरवरी को वीर हकीकत राय बलिदान दिवस मनाया। इस अवसर पर पंजाब प्रांत उपाध्यक्ष सरदार रमेशसिंह और और संगठन मन्त्री श्री सूर्यकान्त केलकर ने हकीकत राय की जीवनी पर प्रकाश डाला।

इसी दिन से निःशुल्क कोचिंग का कार्यक्रम भी शुरू किया गया पंजाब में घातकवादी हलचल के कारण छात्रों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। ऐसी हालत में इस कोचिंग कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। फिलहाल वहाँ विभिन्न कक्षाओं और महाविद्यालयों के 121 छात्र-छात्राएँ कोचिंग ले रहे हैं।

इसी संदर्भ में 19 फरवरी को ए. आई. एस. एस.-एफ (AISSF) द्वारा बार-बार कॉलेज बन्द कराने के विरोध में जिलाधीश को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ए आई एस एस एफ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

Mischievous Treatment to Minorities

[Shri Madandas, All India Organising Secretary addressed a Press Conference at Varanasi on 25th February 1987. The summary of the report appeared in newspapers are hereby reproduced—Ed.]

Addressing the press conference, ABVP's national Organising Secretary Shri Madan Das vehemently criticised the Government for fanning the feeling of separatism by differentiating the Muslim dominated districts in the Education Policy and making them affiliated to the Muslim institutions of higher education. He said that the misconceived selection of 40 Muslim dominated districts for wiping out illiteracy among minorities will lead the entire nation towards separatism in coming future. Instead of involving minorities into the mainstream, the proposed education policy is rather alienating them. It is an object mischief, he added.

Shri Madan Das announced that ABVP will organise a Seminar in August at Varanasi to discuss the implementation of the new-education policy. He declared that the 33rd National Convention of the Parishad would be held in November this year at Agra in which about 5000 students are expected to participate. The main theme would be the implementation of the action plan of New Education Policy. The delay of the 'Operation Black-Board' and 'Job oriented education schemes' were strongly criticised during the press conference. He said that Navodaya Vidyalayas would not bring about any fruitful result unless operation 'black board' scheme achieves success. He said

that Navodaya Vidyalayas would be another kind of public schools where only rich children would get entrance. For most of the schools in the rural areas lack the basic infrastructure and the Government is not in a position presently to provide all possible basic amenities to all the rural schools.

He also criticised the Government for its vague policy on the vocationalisation in education and its total outlay in the field of education. He alleged that the problem of unemployment would increase considerably in coming years because there is no relation between developmental planning and educational planning.

Madanji condemned the recent police atrocities on the BHU students and demanded action against the guilty police personnel. He, however, stressed the need for framing a code of conduct for the students union to avoid professional student leaders, regionalism and vandalism.

He gave details of agitations launched by the Parishad in Maharashtra, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh against political interference, corruption, irregular session and capitation fee etc.

New Education Policy & DMS

— Sanjay Satyarthi

Normal distribution of the Delhi Milk Scheme's (DMS) milk was disrupted as the students went on a one-day token strike and earlier around mid-night deflated tyres of 16 milk vans in different parts of the city. The agitating students broke the windscreens of six vans by hurling stones..an english daily from Delhi reports on 5th March '87.

Reading between the lines, one can easily get the message that youth have become irresponsible, always indulging themselves in destructive activities, completely alienated from social aspirations. On the receiving end, there is no dearth of opinionated preachers—bureaucrats, teachers, businessmen, and ofcourse LEADERS—to be in line of the above message. And to bring this alienated young generation back into healthy tune, all sorts of pshyco-analytical literature, official and non-official, flood-out periodically. New Education Policy is the latest one of such publications, which reads about the role of youth as—'Opportunities should be provided for the youth to involve themselves in national and social development through educational institutions and outside them. (National Policy on Education—1986 Section 8.22 P. 24). Various schemes have been suggested where students will be required to participate. The document further reads 'Government will take special steps to cater to the needs of the deprived sections (should we mean poor students) of societyGraduates will be given opportunities for professional growth, steps will be taken to see that a substantial majority of students are employed or become self-employed (pp. 13-14). Several other tall claims have been made in the

29-page green coloured document. But once the matter comes to a corrupt, unthinking minister and coloured money, the whole scheme of 'youth-inspiration' falls down like a pack of cards. How? Where? & When?

The story goes as follows. The 1,310 milk depots of DMS spread over the capital are manned by about 2,000 students. The students working in these depots are employed by DMS as part-time workers and include students from school as well as colleges. This part-time student employment scheme was started by DMS so that needy low-income group students could work and earn to pay for their education. The senior depot man is paid Rs. 6 per day while a junior student working with him gets Rs 4. A student thus earns Rs, 120-180 per month, a amount sufficient enough to pay his college/school fee. Now, on the instructions from above (unexplained and mysterious too) DMS decided to slowly phase-out the students and employ ex-service men or concessionaries (as they referred to) on payment of Rs. 15 per day. On the face of it, the decision looks simple and absolutely innocent. Nobody can challenge and dare to criticise patriotic concern of the government for ex-servicemen. But the fact of the matter does not suggest so. Informed sources say—a notorious and very strong pressure group is active among ex-servicemen, which manouvours things in the name of exservicemen knowing that society has a sympathetic view towards them. In the process, men in power too make some money which they cannot and never expect to get from students. Narinder Tondon General Secretary, Delhi University Students Union, alleged that the rial

reason for DMS to take away the milk distribution from the hands of students was that certain vested interests in the DMS in collusion with some of the 'concessionaries' employed were running a racket of diverting large quantities of milk of 'halvais'. They, therefore wanted the DMS milk distribution to go to concessionaries. In a meeting with Yogendra Makwana, State Agricultural Minister, Mr Tondon asked him if Government has to provide jobs to ex-servicemen then why don't they do so in other spheres rather than snatch away the bread and butter from needy students. Mr. Makwana shouted back at him saying—'who are you to ask me such questions'. Disappointed and disgusted students came out from that well-guarded ministerial bungalow. Their seventh memorandum (of course each time at a higher level,) was thrown back to them with an unwarranted oral-note—who are you to ask (read—who are you to write & submit this memorandum). The agitated students went for a one-day token strike and the (above quoted) report appeared in the following day newspaper (s). Till the Makwanas are there, no discussion, debate, draft or document initiated and comprehended by Radhakrishnas or Kotharis will be able to tame the 'irresponsible, destructive, unconcerned youth and student mass' howsoever whipping reports appear in news-papers.

Thank God !

Makwana was not the ultimate boss

There is a saying—'keep yourself on the right track, you can't miss the target'. This was true yesterday, this is true today. When beaming student leaders-Narender Tondon (General Secretary—DUSU), Om Prakash Gihara (Convenor DMS Depot Staff Sangharsh Morcha) & Jagat Prakash Nadda (Organising

Secretary, ABVP Delhi State)—came out from the Parliament Office of Union Agriculture Minister Gurudayal Singh Dhillon—the saying reestablished itself in more bright letters.

On 19th March, student delegation had a meeting with Agriculture Minister. After prolonged discussion it was decided that no student will be deprived of his part-time DMS Job. The delegation was further assured that a sympathetic look will be given to other demands viz. enhancement of remuneration etc.

No to Discrimination

ABVP National Secretary Shri Jagat Prakash Nadda issued a press statement condemning the police lathi-charge on African students who were demonstrating against discrimination in regards to AIDS-test (28th February '87).

Mr. Nadda said though such medical test is imperative, the Government's handling of the situation showed lack of proper concern for foreign students. This was not only against the basic stand of the country but would damage the country's credibility abroad.

He appealed to the foreign students to co-operate with the Government for medical tests and added that the same should also be applicable to the non-resident students, who recently returned back to India.

— x —

Dinesh Pahuja, Secretary ABVP Delhi State criticised this Ranguth Mishra Report on Nov. '24 riots. He alleged that to save "some people" the report has been manipulated and many points have not been lightened to this need. He said if this kind of report could not be neutral people will loosefaith on this same, which is dangerous for our soriety.

Foreign Students : Their Problems

Two Russian students who have come to study Hindi and Urdu at Delhi University (both Post-graduates) confess that apart from their work all they do drink tea and sleep. In Russian universities they say, after class most students are involved in some sport or the other, besides which there is always some cultural activity, discussion with scientists and philosophers or some such stimulating activity. With almost nothing of the sort happening at Delhi University, they find tea the most stimulating option, for being scholarship students (on Rs. 600 a month) they can afford little else. They find college education in India lacks orientation as students are not advised on the options available.

In fact there is consensus amongst the foreign students at the International Students Hostel, Mall Road, that for them the university is nowhere near a self-contained unit. Some African students missed a hall with a juke box playing music, which is for them relaxation after classes. Only the monied ones, usually West Asian students could afford an after-class-life, by travelling to Connaught Place or South Delhi.

Social gap

A large number of students come from developing countries. Delhi University having a good reputation in some of these places and being very easily affordable. But after they land here the first thing that strikes them is the social gap between them and most Indian students. One Mauritian student says that having his hair long had incited so much abuse and reaction from Indian students that he went through a mental depression, and in

desperation had his hair cut short. Of course black students have felt the overt colour prejudice and female students' suspicion of them.

They feel that there should be some effort on the part of the authorities to start a campaign for foreign and Indian students to know each other's societies and cultures, to avoid this sort of uneasiness.

They felt the sense of alienation would increase with the AIDS test they were being forced to undergo. The feeling they got was that Indian students generally felt that "foreigners are bad", which would worsen after this issue. Apart from India, according to a report in the International Herald Tribune, Belgium has made AIDS testing for African students compulsory, to the extent of threatening to withhold their university grants if they did not undergo the test.

Foreign students living alienated from the society they have come into say candidly that they have become hostile to it. Some of them also say that Indian society is hypocritical as in functioning as a 'closed society', it does also have a lot of practices that so-called 'permissive societies' have but these are indulged in utmost secrecy.

These students do not have a favourable impression of Indian academic society and have picked out its many loopholes. Says Michael Osusuluwa, a Nigerian student, "It is unheard of to do a Master's degree without doing a thesis in Nigerian universities." He felt that students produced "flashy marks" at the end of the year, studying in little depth, by rote, and grasping hardly anything in the process. He

has stopped impressed with double and triple Master's degrees, having been here years now for under-graduate and post-graduate studies in Political Science. Derecognition of Indian degrees he said had begun in Kenyan and Nigerian unrversities, since the authorities there had caught on to academic standards here.

However that is one sort of opinion for an Oxford graduate, Neil, presently doing sociological studies at Delhi School of Social Work, finds the standards very competitive with Oxford. Of course he is at the advanced research level which would only have students with keenness and interest in their subjects of study and research.

Asked about politicization in the university he felt the climate, as in Oxford, was politically apathetic. The African students however had a lot to say on this score. They recognised 'stooges' of political parties in students, teachers and other bodies and felt that politicking was not constructive because of this. Moreover, political issues many felt were trivial or cosmetic and there was no constructive issue being dealt with, less still any discussions on broader political issues in the world. They had all been attuned to newsletters involving students and getting their views on iasues in their repective countries. Neil, felt it might be a matter of lack of resources here, which made things unorganized, such that more important students' issues and demands never got voiced, and only those like postponement of examinations etc. got student participation.

Foreign students steer clear of Indian students' bodies, being far more comfortable in their own national organisations, which serve as surrogate families in the absence of social interaction with Indians.

Of about 900 foreign students in Delhi, half at least are Africans, from Nigeria,

Kenya, Somalia and Sudan, while other are Palestinians, Iranians, Russians, a few Japanese and Chinese and some other Asian students. Apart from the culture shock on arrival they face a wide range of other problems. Heading straight for the Foreign Students Adviser, they are often met with little or no assistance vis-a-vis information regarding colleges and courses of study. Often students have to change courses after a year, because they were not advised rightly, says a Mauritian student. Moreover they allege rampant corruption with rich students getting hostel rooms, application forms or whatever else they require once they find out the system of functioning.

Waiting lists

At the International Students Hostel, there seems to be anomalous allotment of rooms with people on waiting lists being pre-empted by entries that do not feature on the lists at all. And of the 100 rooms available, 40 have been kept for Indian students, for random allotment to university post-graduates. A Russian student with a weak digestion and on a small value scholarship finds that he might be forced to return to Russia because of such a system. The total mess charge having been paid, he developed a gastric problem and was advised to eat bland, non-greasy food. His request for reimbursement so that he could procure the recommended food from outside has not been met.

The foreign students are seeking improvements all round. They want more assistance in admissions, a more useful Foreign Students Adviser's office, a better reception by Indian students so that they are not alienated from the beginning, and orientation courses on arrival, so that they know what to expect here.